



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 आषाढ़ 1938 (श10)
(सं0 पटना 566) पटना, शुक्रवार, 8 जुलाई 2016

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

15 जून 2016

सं0 22/नि0सि0(डि0)-14-08/2014/1109—श्री गोविन्द प्रसाद (आई0 डी0 -3948), तत्कालीन अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, दुर्गावती दायाँ तट नहर अवर प्रमण्डल सं0-3, मल्हीपुर, शि0-चेनारी द्वारा स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहने, सरकारी कार्य का निष्पादन नहीं करने, नियंत्रण पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना, अनुशासनहीनता एवं नियंत्रण पदाधिकारी के विरुद्ध झूठा एवं अनर्गल आरोप लगाने के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं0 754 दिनांक 19.06.14 द्वारा निलंबित करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय अधिसूचना सं0-2064 दिनांक 23.12.14 द्वारा निम्नांकित आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित की गई:-

- (i) स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहने एवं सरकारी कार्य का निष्पादन कर घर बैठे वेतन पाने की प्रवृत्ति।
- (ii) नियंत्रण पदाधिकारी के आदेश की हमेशा अवहेलना करना एवं पत्राचार में उलझाए रखकर दो वर्षों के सेवाकाल में दुर्गावती जलाशय योजना का कोई कार्य नहीं करना।
- (iii) सरकारी कार्यों के निष्पादन में रूचि का अभाव एवं राजपत्रित पदाधिकारी के आचरण के प्रतिकूल झगडालू एवं अनुशासनहीनता का व्यवहार करना।
- (iv) चेनारी के असामाजिक तत्वों से सौंठ गोंठ कर शिविर में अराजकता की स्थिति पैदा करना एवं दुर्गावती जलाशय योजना के कार्यों के निष्पादन में बाधा उत्पन्न करना।
- (v) नियंत्री पदाधिकारी के विरुद्ध झूठे एवं अनर्गल आरोप लगाकर वरीय पदाधिकारियों से पत्राचार कर उन्हें भयभीत कर बिना सरकारी कार्य निष्पादन के वेतन प्राप्त करने का प्रयास करना।

श्री प्रसाद को विभागीय अधिसूचना सं0-1644 दिनांक 06.11.14 द्वारा निलंबन से मुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी के समक्ष श्री गोविन्द प्रसाद द्वारा कोई बचाव बयान समर्पित नहीं किया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में आरोपों को प्रमाणित पाया गया। प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई एवं संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए विभागीय पत्रांक 2223 दिनांक 30.09.15 द्वारा श्री प्रसाद से द्वितीय कारण पृच्छा की गई। द्वितीय कारण पृच्छा के प्रत्युत्तर में श्री प्रसाद द्वारा बताया गया कि 1,90,000 (एक लाख नब्बे हजार रुपये) की सरकारी राशि के गबन के मामले को नहर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने के योजना हित में खुलासा करने के कारण षड्यंत्र के तहत बन्दरबोत करनेवाले, उच्च रसूख वाले भयादोहन कर प्रत्यानुपातिक धनार्जन करने वाले भ्रष्ट तत्वों से सौंठ गोंठ एवं मिलीभगत कर कतिपय आधारहीन एवं तथ्यहीन आरोपों का उल्लेख कर बिना

Application of mind एवं Mensrea देखे ही विभागीय पत्रांक-8/विविध-10-05/2013-252 दिनांक 17.01.14 एवं 7/परि0-11-1004/12-331 दिनांक 07.04.14 द्वारा पूछे गए स्पष्टीकरण का उत्तर अवर प्रमण्डल के पत्रांक 48 दिनांक 06.03.14 एवं 69 दिनांक 09.05.14 द्वारा समर्पित उत्तर की समीक्षा किए बिना एवं बिना उड़नदस्ता से जाँच कराए प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोप मानकर विभागीय अधिसूचना सं0-754 दिनांक 19.06.14 द्वारा निलंबित कर दिया गया।

श्री प्रसाद पर प्रथम आरोप स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहने एवं सरकारी कार्य का निष्पादन न कर घर बैठे वेतन प्राप्त करने से संबंधित है परन्तु उनके द्वारा इस बिन्दु पर कुछ नहीं कहा गया है और न कोई साक्ष्य दिया गया है जिससे प्रमाणित हो सके कि वे अनुपस्थित नहीं रहे हैं और अपने कर्तव्यों का भली भाँति निर्वहन किया गया है।

अतः आरोप संख्या-1 प्रमाणित है।

आरोप सं0-2 के प्रत्युत्तर में श्री प्रसाद द्वारा बताया गया है कि अनुशासनिक प्राधिकार की राय में उनका (श्री प्रसाद) निलंबन पूर्णरूपेण अनुचित होने के कारण ही चार माह सतरह दिनों के पश्चात निलंबन से मुक्त कर दिया गया।

श्री प्रसाद पर द्वितीय आरोप नियंत्रण पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना एवं पत्राचार में उलझाए रखकर दो वर्षों के सेवाकाल में दुर्गावती जलाशय योजना का कोई कार्य नहीं करने से संबंधित है परन्तु उनके द्वारा अपने प्रत्युत्तर में निलंबन से मुक्त करने के स्थितियों की चर्चा की गई है। आरोप के संबंध में कोई तथ्य अथवा साक्ष्य नहीं दिया गया है जिससे इसका प्रतिवाद हो सके।

अतः आरोप संख्या-2 प्रमाणित है।

आरोप सं0-3 के प्रत्युत्तर में श्री प्रसाद द्वारा बताया कि पूर्णतः निर्दोष होने एवं निलंबित अवधि के पूरे वेतन तथा भत्ता पाने का हकदार होने के कारण निलंबित अवधि के पूरे वेतनादि के भुगतान हेतु दिनांक 13.11.14 को आवेदन दिया था। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 11 (निलंबन के पश्चात पुनः स्थापित किए जाने पर सेवा का निरूपण तथा वेतन भत्ता की अनुमान्यता) के अनुसार उन्हें (श्री प्रसाद) पूरा वेतन एवं भत्ता अनुमान्य है परन्तु आधारहीन एवं तथ्यहीन आरोप लगाकर उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई जिसे निश्चित कालावधि में तार्किक परिणति तक नहीं पहुँचाया गया।

श्री प्रसाद के विरुद्ध आरोप सं0-3 सरकारी कार्यों के निष्पादन में रुचि का अभाव एवं राजपत्रित पदाधिकारी के प्रतिकूल आचरण करने एवं अनुशासनहीनता से संबंधित है परन्तु उनके द्वारा उक्त बिन्दुओं पर अपना प्रत्युत्तर न देकर निलंबन अवधि के वेतनादि भुगतान का मामला उठाते हुए विभागीय कार्यवाही के संचालन पर प्रश्नचिह्न लगाया गया है। निलंबन अवधि के वेतनादि के भुगतान के बिन्दु पर निर्णय बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 11 (5) के तहत विभागीय कार्यवाही के संचालन के पश्चात लिए गए निर्णय के उपरान्त किया जाता है। इस प्रकार श्री प्रसाद द्वारा उनके विरुद्ध प्रमाणित आरोप के बिन्दु पर वस्तुतः कुछ नहीं कहा गया है और न कोई साक्ष्य दिया गया है।

अतः आरोप संख्या-3 प्रमाणित है।

आरोप सं0-4 के प्रत्युत्तर में श्री प्रसाद द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, उड़नदस्ता अंचल-2, पटना से प्राप्त 1,90,000/- (एक लाख नब्बे हजार रुपए) के गबन के मामले से संबंधित जाँच प्रतिवेदन पर कार्रवाई नहीं होने की बात कही गई है।

वस्तुतः उक्त मामला कार्रवाई के अन्तर्गत है और श्री प्रसाद द्वारा अपने विरुद्ध प्रमाणित आरोप के प्रत्युत्तर में कुछ नहीं कहा गया है।

अतः आरोप संख्या-4 प्रमाणित है।

आरोप सं0-5 के प्रत्युत्तर में श्री प्रसाद द्वारा मुख्यतः संचालन पदाधिकारी पर उनसे गलत लाभ प्राप्त करने की मंशा का आरोप लगाया गया है तथा विभागीय कार्यवाही का संचालन सही तरीके से नहीं करने की बात कही गई है। इसके साथ ही अपने वरीय एवं अधीनस्थ पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों पर विभिन्न तरह के आरोप लगाते हुए विभाग की कार्य प्रणाली पर प्रश्नचिह्न लगाया गया है।

श्री प्रसाद के विरुद्ध आरोप सं0-5 नियंत्री पदाधिकारी के विरुद्ध झूठे एवं अनर्गल आरोप लगाकर वरीय पदाधिकारियों से पत्राचार कर उन्हें भयभीत कर बिना कार्य निष्पादन के वेतन प्राप्त करने का प्रयास से संबंधित है जिसके प्रत्युत्तर में श्री प्रसाद द्वारा अपना पक्ष न रखकर संचालन पदाधिकारी, वरीय पदाधिकारी एवं अधीनस्थों के विरुद्ध दोषारोपण किया गया है जो आरोप सं0-5 को स्वतः प्रमाणित करता है।

श्री गोविन्द प्रसाद, तत्कालीन अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, दुर्गावती दायें तट नहर अवर प्रमण्डल सं0-3, मल्हीपुर, शि0-चेनारी से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के प्रत्युत्तर की सम्यक समीक्षोपरान्त प्रमाणित आरोपों के आलोक में उनके विरुद्ध निम्नांकित दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय सरकार के स्तर से लिया गया है:-

(i) निन्दन वर्ष 2013-14

(ii) दो वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।

दण्ड प्रस्ताव की कंडिका-(ii) पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक 682 दिनांक 02.06.16 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

अतः सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री गोविन्द प्रसाद (आई० डी० -3948), तत्कालीन अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, दुर्गावती दायाँ तट नहर अवर प्रमण्डल सं०-3, मल्हीपुर, शि०-चेनारी को निम्न दण्ड दिया एवं संसूचित किया जाता है।

(i) निन्दन वर्ष 2013-14

(ii) दो वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

जीउत सिंह,

सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 566-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>